1	2	3	4
3.	अहमदाबाद (गुजरात, संघ शासित क्षेत्र दीव-दमन)	114.71	121.48
4.	मद्रास (तमिल नाडु, आन्ध्र प्रदेश, संघ-शासित क्षेत्र पांडिचेरी, करैकल व यनम)	21.32	26.23
5.	बम्बई (महाराष्ट्र, कर्नाटक)	8.39	8.34
6.	कलकत्ता (पश्चिम बंगाल, उड़ीसा)	1.26	1.05
	योग	158.13	169.89

विवरण-III

विकास संबंधी तथा श्रमिक कल्याण कार्यों पर किया गया व्यय

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	क्षेत्र	व्यय 1986-87	1987-88
1.	जोधपुर	18.54	3.36
2.	अहमदाबाद	5.27	22.65
3.	मद्रास	32.58	49.54
4.	बम्बई	7.25	9.11
5.	कलकत्ता	6.01	8.61
	योग	69.65	93.27

सरकारी तथा निजी कम्पनियों द्वारा ट्रैक्टरों का उत्पादन

519. **श्री मीर्जा इर्शादबेग** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी सरकारी तथा निजी कम्पनियां ट्रैक्टरों का उत्पादन करती हैं और इनका प्रति वर्ष कितना उत्पादन होता है ;

(ख) छोटे ट्रैक्टरों के उत्पादन करने संबंधी क्या कोई समिति का गठन हुआ था और यदि हां, तो उसके प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है और कब तक ये प्रतिवेदन सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा; और

(ग) इस संबंध में सरकार का आगामी आयोजन क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) इस समय ऐसे 17 एकक हैं जो ट्रैक्टर उत्पादन की सूचना दे रहे हैं, इनमें से 4 सरकारी क्षेत्र (केन्द्र सरकार तथा

राज्य सरकारों दोनों से संबंधित) के हैं और 13 एकक गैर सरकारी क्षेत्र में हैं।

पिछले 3 वर्षों में हुये उत्पादन के आंकड़े निम्नलिखित हैं:—

	सरकारी क्षेत्र	गैर सरकारी क्षेत्र	कुल
1985–86	14,841	60,621	75.462
1986–87	15,509	64,964	80,473
1987–88	16,949	74,398	91,347

(ख) और (ग) छोटे ट्रैक्टर बनाने के बारे में सरकार ने कोई समिति गठित नहीं की है। किन्तु ट्रैक्टर बनाने वाले बहुत से प्रमुख निर्माता छोटे ट्रैक्टर बना रहे हैं और बाजार में इस प्रकार के ट्रैक्टरों की कमी नहीं है। सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार, अपना लाइसेंसशुदा क्षमता के भीतर निर्माता किसी भी प्रकार के ट्रैक्टरों का उत्पादन कर सकते हैं।

Illegal mining of coal to Bihar

520. SHRI YASHWANT SINHA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the fact that illegal mining of coal is rampant in Hazaribagh district of Bihar, especially in the Ramgarh and Mandu police stations;

(b) whether it is a fact that several truck loads of this illegally mined coal are moved out of this area by road every day in collusion with local officials; and

(c) what steps Government propose to take to put an end to this malpractice?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF COAL IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI C. K. JAFFAR SHARIEF): (a) to (c) There is no organised illegal coal mining in the leased hold areas of the coal companies. However, as the coal belt in the country is vast, certin persons at times violate the provisions of law and indulge in illegal extraction of coal sporadically and stealthily.

The Coal Mines Nationalisation Acts were amended in 1976 making illegal coal mining a cognizable offence, punishable with imprisonment extending upto 3 years, and fine extending upto Rs. 20,000. The vires of these amendments have already been upheld by the Supreme Court in 1980.

The State Governments have been asked to take both punitive and preventive action against the offenders in terms of the Nationalisation Acts read with provisions of the Indian Penal Code. The State Governments in turn had already issued instructions to the District Authorities. The coal companies have been directed to report the cases of illegal extraction of coal as and when detected by them to the law enforcing authorities in the States. Besides, the coal companies in conjunction with the State Government's law enforcing authorities in the State conduct regular raids to apprehend offenders.

Soviet assistance for development of Thermal Power Projects

521. SHRI YASHWANT SINHA:
SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE:

Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have entered into a long term agreement with the Soviet Union for securing assistance in the development of Thermal Power Projects in the country; and

(b) if so, what are the details thereof?